भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: †2257
12 दिसंबर, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उक्तर

कर्नाटक में स्वास्थ्य संबंधी अनुदान का उपयोग

†2257. कैप्टन बृजेश चौटा:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2021-22 से अब तक कर्नाटक राज्य को 15वें वित्त आयोग स्वास्थ्य अनुदानों के अंतर्गत जारी कुल धनराशि का दक्षिण कन्नड़ सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त राज्य में इन अनुदानों की उपयोगिता की स्थिति सहित पूर्ण और लंबित परियोजनाओं की संख्या क्या है तथा इसमें हुए विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने दक्षिण कन्नड़ सहित अन्य जिलों में अनुदानों के कम उपयोग की समीक्षा की है, यदि हाँ, तो अनुशंसित सुधारात्मक उपायों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त अनुदानों के तहत स्वीकृत और वर्तमान में क्रियात्वित किए जा रहे प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल संबंधी अवसंरचना कार्यों के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

<u>उत्तर</u>
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): पंद्रहवें वित्त आयोग (एफसी 15वां) के अंतर्गत कर्नाटक राज्य के लिए कुल आवंटन एवं जारी की गई निधि का विवरण इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए में)

अवधि	आवंटन की अवधि **2021-22**	जारी की गई निधि
आवंटन की अवधि 2021-22	551.53	551.53
आवंटन की अवधि 2022-23	551.53	551.24
आवंटन की अवधि 2023-24	579.11	395.02
आवंटन की अवधि 2024-25	608.08	0.00
आवंटन की अवधि 2025-2026	638.48	0.00
आवंटन की अवधि 2021-2026	2,928.73	1,497.79

(ग) और (घ): स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार (एमओएचएफडब्ल्यू) कर्नाटक राज्य सहित पूरे देश में स्वास्थ्य सुविधा-केन्द्रों की उपलब्धता की नियमित रूप से समीक्षा करता है। यह समीक्षा मुख्यतः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) और इसकी प्रमुख कार्यनीतियों के कार्यान्वयन की स्थिति की समीक्षा के लिए वार्षिक रूप से आयोजित सामान्य समीक्षा मिशन (सीआरएम) के माध्यम से की जाती है। प्रमुख प्रदेयों की समीक्षा एनपीसीसी बैठकों और मध्यावधि समीक्षा बैठकों में भी की जाती है।

कर्नाटक राज्य सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राज्य सरकार ने जिला स्वास्थ्य अधिकारियों को 15वें वित्त आयोग के सभी छह घटकों के तहत जिलों को आवंटित निधि के कार्यान्वयन और उपयोग की निगरानी करने का निर्देश दिया है। 15वें वित्त आयोग की निधि के आवंटन और उपयोग की समीक्षा सभी जिलों के उपायुक्तों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की अर्धवार्षिक बैठक में की गई। इसके अलावा, 15वें वित्त आयोग पर राज्य स्तरीय समिति द्वारा प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं, जहां सभी कार्यान्वयन विभागों की प्रगति की समीक्षा की जाती है। साथ ही, माननीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा समय-समय पर जिलों में प्रगति समीक्षा बैठकें आयोजित की जाती हैं।

*****